सामाजिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण परिणाम
महाराष्ट्र

दिसंबर 2019

वित्तीय स्थिति

रसीदें

- वित्तीय वर्ष 2017-18 (A) और वित्तीय वर्ष 2018-19 (RE) के बीच राजस्व प्राप्तियों में 18 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2018-19 (RE) और वित्तीय वर्ष 2019-20 (BE) के बीच यह संख्या 10 प्रतिशत और बढ़ गई। इसी अवधि में महाराष्ट्र राज्य को हस्तांतरित केंद्रीय कर राजस्व में 12 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

.

- वित्तीय वर्ष 2017-18 (A) और 2018-19 (RE) के बीच, स्वयं-कर राजस्व में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2018-19 (RE) और 2019-20 (BE) के बीच, इसमें 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राजस्व प्राप्तियां (करोड़ में)							
	2014-15 (A)	2015-16 (A)	2016-17 (A)	2017-18 (A)	2018-19 (BE)	2018-19 (RE)	2019-20 (BE)
केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	19,778	30,279	36,027	39,409	45,315	44,250	48,831
सहायता अनुदान (जी-आई-ए)	20,141	16,899	21,653	21,823	31,629	38,468	40,227
स्वयं कर राजस्व	1,12,915	1,24,435	1,34,304	1,65,742	1,86,240	1,86,731	2,08,624
स्वयं गैर-कर राजस्व	12,581	13,423	12,709	16,680	22,785	17,050	16,807
कुल राजस्व प्राप्तियां	1,65,415	1,85,036	2,04,693	2,43,654	2,85,968	2,86,500	3,14,489

वित्त वर्ष 2019-20 (BE) में राजस्व प्राप्तियां

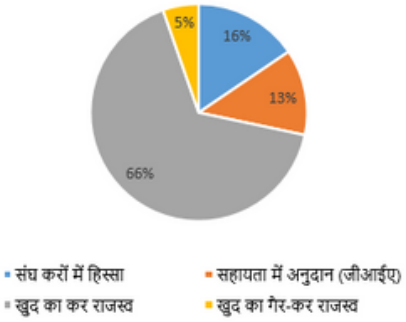

व्यय

- वित्तीय वर्ष 2018-19 (RE) में महाराष्ट्र का व्यय पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़ों से 28 प्रतिशत अधिक रहा। वित्तीय वर्ष 2019-20 (BE) में यह बढ़कर तीन करोड़ पचहत्तर लाख और छह रुपये (3, 75, 006 करोड़ रुपये) हो गया, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान का 9 प्रतिशत है। इसका कारण सामाजिक सेवाओं पर बढ़ता व्यय है।

- वित्तीय वर्ष 2017-18 (A) और वित्तीय वर्ष 2018-19 (RE) के बीच, सामाजिक सेवाओं पर खर्च में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 (BE) में, सामाजिक सेवाओं पर व्यय पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 12 प्रतिशत अधिक हुआ।

स्रोत: यह दस्तावेज़ Accountability Initiative, Centre for Policy Research के बजट ब्रीफ श्रृंखला से बनाया गया है। अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर जाएँ: https://accountabilityindia.in/budget-brief।

महाराष्ट्र के बजट में व्यय (करोड़ में)							
व्यय का प्रकार	2014-15 (A)	2015-16 (A)	2016-17 (A)	2017-18 (A)	2018-19 (BE)	2018-19 (RE)	2019-20 (BE)
कुल व्यय	1,97,077	2,13,167	2,38,778	2,68,413	3,37,641	3,43,032	3,75,006
राजस्व व्यय	1,77,553	1,90,374	2,13,229	2,41,571	3,01,343	3,01,460	3,34,273
पूंजीगत व्यय	19,523	22,793	25,549	26,842	36,298	41,573	40,732
सामान्य क्षेत्र का व्यय	61,351	65629	73,158	79,583	1,01,424	90,916	1,09,373
सामाजिक क्षेत्र का व्यय	78,910	84,901	93,548	95,323	1,27,817	1,34,917	1,51,508
अवशिष्ट क्षेत्र व्यय	56,815	62,637	72,072	93,508	1,08,400	1,17,200	1,14,125

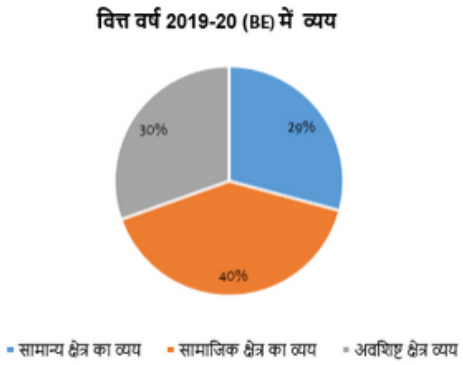

सामाजिक क्षेत्र का व्यय

- सामाजिक क्षेत्र के व्यय में वित्तीय वर्ष 2018-19 (RE) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 (A) के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वृद्धि तीन क्षेत्रों में हुई है, जो हैं: 'जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास' 81 प्रतिशत से; 'ग्रामीण विकास' 89 प्रतिशत से; 'सूचना और प्रसारण' 100 प्रतिशत से। वित्तीय वर्ष 2019-20 (BE) में, इन क्षेत्रों में पिछले वर्षों के संशोधित अनुमान की तुलना में क्रमशः 26 प्रतिशत, 61 प्रतिशत और 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

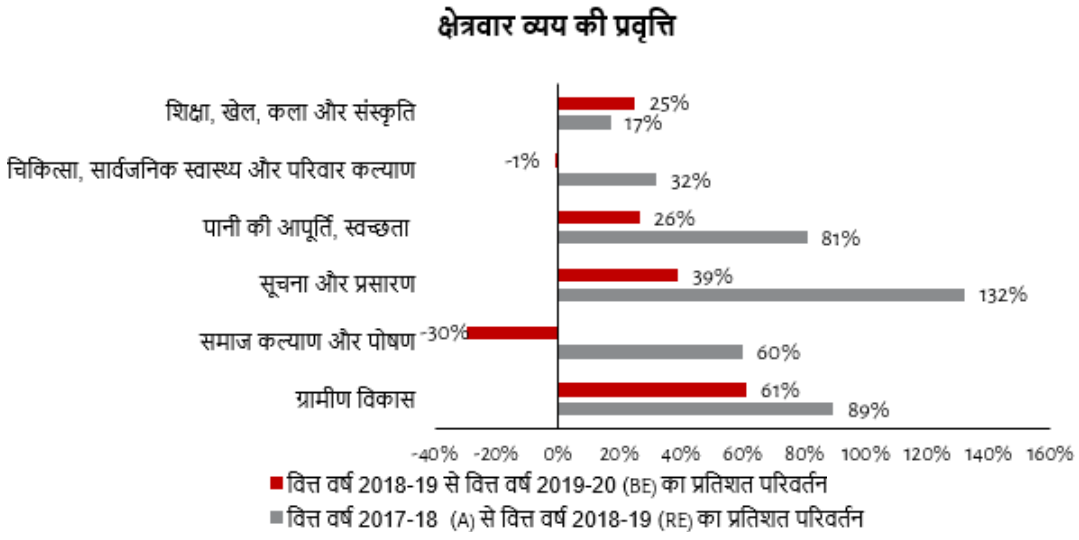

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन - ग्रामीण

- ग्रामीण भारत में सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य व देखभाल प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) 2005 में शुरू किया गया।

फंड की स्थिति

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के लिए भारत सरकार द्वारा पिछले साल, वित्तीय वर्ष 2018-19 (RE) में 56,045 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, जो की वित्तीय वर्ष 2019-20 (BE) में 15 प्रतिशत से बढ़कर 64,559 करोड़ रुपये हो गया है।

- वित्तीय वर्ष 2019-20 (BE) में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 32,995 करोड़ रुपये आवंटित किए जो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 (RE) के 30,683 करोड़ रुपये के मुकाबले 8 प्रतिशत की वृद्धि है। इस वृद्धि का एक कारण है स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के आवंटन में हुई 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी।

- वित्तीय वर्ष 2017-18 में महाराष्ट्र राज्य कोषागार से राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को धन हस्तांतरित करने में औसतन 95 दिन लगे थे, जबकि 2015-16 में औसतन 66 दिनों में यह हस्तांतरण हुआ था, यानि कम दिन लगे थे।

- **व्यय**: कुल बजट के अनुपात में व्यय कम रहा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कुल बजट का 45 प्रतिशत खर्च हुआ था, जो कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में और घटकर कुल बजट का 42 प्रतिशत ही रहा। खर्च की यह दर भारत के सारे राज्यों की औसत दर से 59 प्रतिशत कम थी।

प्रदर्शन

वर्ष 2018 में महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पताल के प्रति बिस्तर पर आबादी की औसत दर:

प्रति 4,965 आबादी के लिए एक बेड

भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (IPHS) मानदंडों के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHCs) के कामकाज में महाराष्ट्र ने वृद्धि दर्ज की है।

स्रोत: रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स, 2018

समग्र शिक्षा

- समग्र शिक्षा भारत सरकार की सबसे बड़ी शिक्षा योजना है जो कि अप्रैल 2018 में शुरू की गयी थी। इसका उद्देश्य पूर्व प्राथमिक से उचितर माध्यमिक कक्षाओ तक समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें तीन पूर्व योजनाये शामिल है: सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और शिक्षक प्रशिक्षण।

फंड की स्थिति

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में समग्र शिक्षा के लिए 30,781 करोड़ रुपये (RE) आवंटित किए गए । महाराष्ट्र के प्रस्तावित बजट में से केवल 57 प्रतिशत को ही भारत सरकार की मंज़ूरी मिली (स्पिलओवर को मिलाकर)। यह हमारे विश्लेषण किये गए 18 राज्यों में से सबसे कम था।
  - वित्तीय वर्ष 2018-19 की शुरुआत में महाराष्ट्र की स्पिलओवर की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत थी। हमने पाया कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब ऐसे राज्य थे, जिनकी हिस्सेदारी सबसे अधिक थी।
    - स्पिलओवर उस राशि को कहते हैं जो पिछले साल की अनुमोदित राशि में से खर्च नहीं हो पायी) है । यह अगले साल की अनुमोदित राशि में जुड़ जाती है।

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य ने समग्र शिक्षा आवंटित बजट का 75 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिक शिक्षा को, 23 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा को और 2 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षण को दिया।

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रारंभिक शिक्षा में प्रति बच्चे के लिए आवंटन 1,633 रुपये थी। यह राशि उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए 1,081 रुपये थी।

- **व्यय**: सिर्फ **58 प्रतिशत** वित्तीय वर्ष 2018-19 के कुल मंजूर बजट में से खर्च किया गया।
  - प्रारंभिक शिक्षा में प्रति बच्चे के आवंटन में से 1,022 रुपये खर्च किया गया।
  - उच्च माध्यमिक में प्रति बच्चे के आवंटन में से केवल 485 रुपये खर्च किया गया।

सीखने के प्रतिफल- महाराष्ट्र

कक्षा 8 के गणित में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या :

19%

कक्षा 10 के गणित में 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या:

7%

कक्षा 10 के साइंस में 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या :

10%

एकीकृत बाल विकास सेवायें (कोर)

- एकीकृत बाल विकास सेवायें (ICDS) भारत सरकार का प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्रदान करने वाला प्रमुख कार्यक्रम है | योजना का उद्देश्य 6 वर्ष की आयु से नीचे बच्चों की मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्तियों को कम करना है | साथ ही इसका उद्देश्य माताओं की क्षमताओं में वृद्धि करना है, जिससे वे अपने बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा कर सकें|

फंड की स्थिति

- एकीकृत बाल विकास सेवायें (कोर) यानि कि आंगनवाड़ी सेवा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) द्वारा संचालित सबसे बड़ी योजना है | वित्तीय वर्ष 2019-20 (BE) में, 19,834 करोड़ रुपये आंगनवाड़ी को आवंटित किये गए जो कि पिछले साल के मुकाबले 11 प्रतिशत अधिक है [वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन 17,890 करोड़ रुपये (RE) था]|
- महाराष्ट्र के लिए 2017-18 और 2018-19 के बीच भारत सरकार का अनुमोदित बजट 14 प्रतिशत बढ़ा|
- ICDS बजट में दो मुख्य घटक होते हैं: a) पूरक पोषण कार्यक्रम (SNP) और b) ICDS-सामान्य| हमारे विश्लेषण किये गए 19 राज्यों में से SNP के लिए जारी राशि महाराष्ट्र में सबसे अधिक थी| ICDS-सामान्य के लिए भारत सरकार ने स्वीकृत राशि का 111 प्रतिशत जारी किया|

कवरेज

मार्च 2014 और मार्च 2019 के बीच में SNP लाभार्थियों के प्रतिशत में 15% की गिरावट दर्ज हुई | इसी दौरान पूर्व विद्यालयी शिक्षा (PSE) के लाभार्थियों में 15% की गिरावट दर्ज की गयी|

मार्च 2019 तक प्रति चालू आंगनवाड़ी केंद्र 3-6 वर्ष आयु के 23 बच्चों को PSE प्राप्त करवा रहा था | यह आंकड़ा SNP पाने वाले बच्चों (6 माह से 6 वर्षीय तक) के लिए 47 था|

मार्च 2019 तक महाराष्ट्र में 55% बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) के पद रिक्त थे | हमारे विश्लेषण किये गए राज्यों में महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में CDPO के पद सबसे अधिक रिक्त थे | वहीँ 22% लेडी सुपरवाइजर (LS) के पद रिक्त थे|

आंगनवाड़ी केंद्र जिनमें पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है:

95% में उपलब्ध

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन

- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन (NRDWM) भारत सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षित पेयजल और अन्य घरेलू ज़रूरतों को स्थायी आधार पर प्रदान करने की प्रमुख योजना है|

फंड की स्थिति

- वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन कर दिया| वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल आवंटित धन का 94 प्रतिशत जारी किया गया था, जहाँ वित्तीय वर्ष 2018-19 में, कुल धन का 90 प्रतिशत आवंटित धन जारी किया गया था|
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलब्ध कुल धन में से 51 प्रतिशत ही खर्च किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह बढ़कर 57 प्रतिशत हो गया|

कवरेज

जबकि महाराष्ट्र में 40 lpcd मानदंड के अनुसार कवरेज 85 प्रतिशत था, वही 55 lpcd मानदंड के प्रयोग से गिरकर 3 प्रतिशत हो गया|

28 जून 2019 तक 38 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों के घरों में पानी की आपूर्ति वाले कनेक्शन (PWS) लगे हुए थे|

2017-18 में ग्राम पंचायत को सौंपी गई लक्षित PWS योजना 93 प्रतिशत थी| 2018-19 में ग्राम पंचायत को सौंपी गई लक्षित PWS योजना 98 प्रतिशत थी|

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) भारत सरकार द्वारा 2006 में शुरू की गई थी, ताकि रोजगार की मांग के आधार पर ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा संचालित सबसे बड़ी योजना है।

फंड की स्थिति

- वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक मनरेगा का क्रमश: आवंटन बढ़ता रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2019-2020 में थोड़ी कमी देखी गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में, वर्ष के पहले तीन महीनों के भीतर, कुल बकाया भुगतान 2,735 करोड़ रुपये था।
- 2018-19 में मटेरियल कॉस्ट आठ गुना तक बढ़ गया है। मनरेगा में काम की मांग ज्यादा है, पर मांग के अनुसार मजदूरी कम दी जा रही है।
- 2019-20 में पिछला बकाया एवं उपलब्ध राशी का कुल व्यय, 74 प्रतिशत हुआ है।

प्रदर्शन

वर्ष 2018-19 के लिए राज्य की अधिसूचित मजदूरी दर

203 रुपये

वर्ष 2018-19 में ग्रामीण घरों में प्रति व्यक्ति कार्य दिवस

47 दिन

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्य पूरा होने की दर 54% से घटकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में

26% हो गयी

स्वच्छ भारत मिशन

- स्वच्छ भारत मिशन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित योजना है, जिसके उद्देश्य हैं: स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच, ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता का प्रोत्साहन और खुले में शौच की प्रथा को 2019 तक समाप्त करना।

फंड की स्थिति

- वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2017-18 तक केंद्रीय सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को आवंटन में काफी वृद्धि देखी गयी थी, किन्तु 2018-19 से अभी तक, यह राशि कम होती जा रही है। इस साल की राशि 9,994 करोड़ रुपये थी, जो की पिछले साल से 31 प्रतिशत कम है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्रीय सरकार ने शहरी मिशन को 2,650 करोड़ रुपये आवंटित किया। पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान (RE) के मुकाबले यह 6 प्रतिशत की वृद्धि है।
- 12 जून 2019 तक महाराष्ट्र का प्रति दिन कचरा उत्पादन सबसे ज़्यादा था (22,570 मीट्रिक टन), जो की कुल अपशिष्ट (waste) का 16 प्रतिशत था (राष्ट्रीय स्तर पर प्रति दिन 1.45 लाख मीट्रिक टन उत्पादित)। यह 30 सितंबर 2019 तक 23,450 मीट्रिक टन पहुंच गया। लेकिन 31 जनवरी 2019 तक महाराष्ट्र को ठोस अपशिष्ट से निपटने के लिए आवंटित धन में से केवल 37 प्रतिशत प्राप्त हुआ।

प्रदर्शन

महाराष्ट्र 19 अप्रैल 2018 को खुले में शौच से मुक्त (ओपन दफेकशन फ्री) घोषित कर दिया गया था।

100% गांवों की पहली ODF जांच हो चुकी है, किंतु 0% गांवों की दूसरी दफा जांच हुई है।

व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का प्रमुख निर्माण 2017-18 में हुआ था।

महाराष्ट्र द्वारा सूचना, शिक्षा, संचार गतिविधियों पर 2018-19 में कुल खर्च

3%

31 जनवरी 2019 तक, कुल सूचना, शिक्षा, संचार गतिविधियों के लिए केवल 20% धनराशि जारी की गयी। इसमें से 77% धनराशि, 31 जनवरी 2019 तक उपयोग की गयी, जो राष्ट्रीय औसत से 67% ऊपर है।